

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,  
लोक निर्माण विभाग,  
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक: 24 सितम्बर, 2014

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत अनुदान सं०-22 आयोजनागत पक्ष की राज्य योजनान्तर्गत निर्माणाधीन मार्ग कार्य की मद में धनराशि स्वीकृत किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं०- 5783/01 बजट (मार्ग चालू कार्य-रा०से०)/2014-15 दिनांक 16-09-2014 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश सं०- 2261/111(2)/14-01(बजट)/2014 दिनांक 07 अप्रैल, 2014, शासनादेश सं०- 4232/111(2)/14-01(बजट)/2014 दिनांक 14 जुलाई, 2014, शासनादेश सं०-5251/111(2)/14-09(रिट याचिका)/2014 दिनांक 15 सितम्बर, 2014 तथा अपर मुख्य सचिव, वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं०- 318/XXVII(1)/2014 दिनांक 18 मार्च, 2014 एवं पत्र सं०- 622/XXVII(1)/2014 दिनांक 26 जून, 2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान सं०-22 राज्य योजनान्तर्गत आयोजनागत पक्ष में निर्माणाधीन मार्ग चालू कार्य की मद में धनराशि की आवश्यकता के दृष्टिगत ₹ 22.30 करोड़ ( ₹ बाईस करोड़ तीस लाख मात्र) धनराशि व्यय हेतु, आपके निर्वतन पर रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(i)- उक्तानुसार अवमुक्त की जारी रही धनराशि के सापेक्ष सी०सी०एल आवंटन, खण्डवार स्वीकृत कार्यों की कार्यवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए कार्य की प्रगति तथा कार्य की तात्कालिक आवश्यकता, के आधार पर की जायेगी तथा इसकी सूचना शासन को भी प्रेषित की जायेगी।

(ii)- उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण वितरण अधिकारी द्वारा बी०एम०-4 प्रपत्र पर रखा जायेगा और पूर्व के माह के व्यय का विवरण अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल के अध्याय-12 के प्रस्तर-101 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा और प्रस्तर-113 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी (मुख्य अभियन्ता, लो०नि. वि०) द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा। प्रशासनिक विभाग बजट मैनुअल के प्रस्तर-115 के अधीन उक्त आवंटित धनराशि के व्यय का नियंत्रण करेंगे।

(iii)- आयोजनागत पक्ष की संलग्न योजनाओं की सी०सी०एल० प्रत्येक त्रैमास में समय से निर्गत कर उसकी प्रति प्रत्येक त्रैमास में शासन को भी प्रेषित की जायेगी। विभागाध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि प्रत्येक खण्ड से समय से योजनाओं का विवरण प्राप्त करके समय से उसकी साख सीमा निर्गत कराये ताकि स्वीकृत की जा रही धनराशि का समय से उपयोग हो सके और योजना का लाभ जनता को प्राप्त हो सके। इस सम्बन्ध में उत्तरदायी अधिकारी के द्वारा विलम्ब से विभागाध्यक्ष को योजनाओं का विवरण सूचित करने के कारण सी०सी०एल० निर्गत करने में विलम्ब होता है तो उसका स्पष्टीकरण प्राप्त कर ठोस कारण न होने पर उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी और लगातार दो बार योजनाओं का विवरण समय से न भेजे जाने के कारण यदि पुनः सी०सी०एल० निर्गत करने में विलम्ब होता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। मुख्य अभियन्ता का यह भी दायित्व होगा कि विभागीय योजनाओं की समय से समीक्षा कर समय से प्रतिशत के अनुसार सी०सी०एल० निर्गत करेंगे।

(iv)- सर्वप्रथम उन निर्माणाधीन कार्यों का पूर्ण किया जाय, जिसमें 75 प्रतिशत का कार्य पूर्ण हो चुका है। तत्पश्चात् 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक पूर्ण हो चुके कार्यों का वरीयता दी जाये।

(v)- वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड V भाग-1 के प्राविधानों के सभी समस्त औपचारिकतायें पूर्ण होने के बाद ही आवश्यकता के अनुसार धनराशि आवश्यकता होने पर ही आहरित एवं वितरित की जायेगी।

(vi)- इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं०-318/XXVII(1)/2014 दिनांक 18-03-2014 में उल्लिखित शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(vii)- उत्तराखण्ड में लागू समस्त वित्तीय नियमों तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2008 के अधीन ही समस्त प्रक्रियायें पूर्ण की जायेंगी तथा ऐसे कार्य जो मानक के अनुसार 18 माह में पूर्ण होने चाहिये, ऐसे प्रकरणों में अधिवृद्धि या शेड्यूल रेट्स की दरों में कोई वृद्धि नहीं की जायेगी।



(viii)– साख सीमा मानक के अनुसार प्रत्येक त्रैमास में निर्गत की जायेगी तथा यदि मानक से अधिक साख सीमा की आवश्यकता हो तो तत्काल शासन से इस सम्बन्ध में अनुमति प्राप्त की जायेगी।

(ix) साख सीमा के आधार पर आवंटित धनराशि का एकमुश्त आवंटन आहरण वितरण अधिकारी/कार्य स्थल पर किया जाय एवं उसका पूर्ण विवरण बजट मैनुअल के प्रस्तर-10 में भरकर शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(x)– जिन प्रकरणों पर शासन से पूर्वानुमति की आवश्यकता हो उन पर यथाशीघ्र सुस्पष्ट विवरण एवं प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(2)– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्यय के अनुदान सं०:-22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-01 चालू निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(3)– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं०:-318/XXVII(2)/2014 दिनांक: 18 मार्च, 2014 एवं पत्र सं०:-622/XXVII(1)/2014 दिनांक 26 जून, 2014 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय

( अमित सिंह नेगी )  
सचिव।

संख्या-5308 (1)/111(2)/14-01(बजट)/2014 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा प्रथम) ओबर्ग मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
- 2- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 3- एकीकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय (साईबर ट्रजरी), 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
- 4- वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड देहरादून।

आज्ञा से,

( ललित मोहन आर्य )  
संयुक्त सचिव।